

कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय की हिंदी सलाहकार समिति की दिनांक 01.08.2023 को सायंकाल 06 बजे नई दिल्ली स्थित संसदीय सौंध के समिति कक्ष 'सी' में आयोजित पहली बैठक का कार्यवृत्त:-

कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्री श्री धर्मेन्द्र प्रधान जी की अध्यक्षता में मंत्रालय की हिंदी सलाहकार समिति की पहली बैठक का आयोजन दिनांक 01.08.2023 को सायंकाल 06 बजे नई दिल्ली स्थित संसदीय सौंध के समिति कक्ष 'सी' में किया गया। बैठक में उपस्थित सदस्यों की सूची अनुलग्नक-1 पर संलग्न है।

1. बैठक की कार्यवाही का आरंभ मंत्रालय के सचिव श्री अतुल कुमार तिवारी द्वारा माननीय मंत्री जी श्री धर्मेन्द्र प्रधान, राज्य मंत्री श्री राजीव चंद्र शेखर व माननीय सांसद श्री रमेश बिधूड़ी, श्री आदित्य प्रसाद, श्री सिकंदर कुमार तथा उपस्थित विद्वान सदस्यों के स्वागत से किया गया। अपने स्वागत संबोधन में सचिव ने समिति को बताया कि कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय नवंबर 2014 में अस्तित्व में आया। मंत्रालय का प्रमुख कार्य-दायित्व विभिन्न स्कीमों/कार्यक्रमों के माध्यम से संपूर्ण भारत वर्ष के युवाओं का कौशलीकरण करना है ताकि वे अपने-अपने कार्य क्षेत्र में कुशलता प्राप्त कर रोजगार प्राप्त कर सकें अथवा स्वयं का उद्यम स्थापित कर आत्मनिर्भर बन सकें। मंत्रालय अपने व्यावसायिक कार्य की तरह ही राजभाषा हिंदी के कार्यान्वयन की दिशा में प्रतिवद्ध है और राजभाषा विभाग के वार्षिक कार्यक्रम में निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए भरपूर प्रयास कर रहा है। उन्होंने मंत्रालय में विगत तीन वर्षों के दौरान हिंदी के प्रयोग में हुई प्रगति का संक्षिप्त ब्योरा समिति के समक्ष रखा। उन्होंने आगे कहा कि यह हर्ष का विषय है कि आज मंत्रालय की हिंदी सलाहकार समिति की पहली बैठक आयोजित हो रही है और इस बैठक में जो भी सुझाव आएंगे, उनका अनुपालन करने के लिए हम प्रयासरत रहेंगे।

2. मंत्रालय की संयुक्त सचिव (राजभाषा एवं समन्वय) डॉ. सुपर्णा एस. पचौरी द्वारा पीपीटी के माध्यम से मंत्रालय में राजभाषा के प्रयोग की दिशा में किए जा रहे विभिन्न कार्यकलापों का विवरण समिति के समक्ष प्रदर्शित किया गया। उन्होंने समिति को अवगत कराया कि मंत्रालय किस तरह विगत तीन वर्षों के दौरान राजभाषा अधिनियम 1963 तथा राजभाषा नियम 1976 के प्रावधानों का अनुपालन करने में उत्तरोत्तर प्रगति कर रहा है। उन्होंने सचिव महोदय द्वारा प्रस्तुत संक्षिप्त विवरण को पीपीटी के माध्यम से विस्तार से प्रस्तुत किया जिसके प्रमुख बिंदु निम्नानुसार हैं:-

1. मंत्रालय की हिंदी की तिमाही प्रगति रिपोर्ट व वार्षिक मूल्यांकन रिपोर्ट राजभाषा विभाग की वेबसाइट पर नियमित रूप से अपलोड की जा रही है।
2. मंत्रालय के 4 प्रमुख अनुभागों को शत-प्रतिशत कार्य हिंदी में करने के लिए राजभाषा नियम, 8(4) के अंतर्गत विनिर्दिष्ट किया गया है।
3. मंत्रालय के सभी कंप्यूटरों में यूनिकोड हिंदी मंगल इंस्क्रिप्ट फॉन्ट सक्रिय करवा दिए गए हैं।
4. पिछले दो वर्षों के दौरान मंत्रालय के 16 अधीनस्थ कार्यालयों का राजभाषा विषयक निरीक्षण किया गया।
5. मंत्रालय के 26 प्रवीणता प्राप्त अधिकारियों को अपना सरकारी कार्य हिंदी में करने के लिए व्यक्तिशः आदेश जारी किए गए और इसके परिणामस्वरूप हिंदी कामकाज में आशातीत वृद्धि हुई है।
6. मंत्रालय में कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों की हिंदी में कार्य करने की झिझक दूर करने के लिए पिछले तीन वर्षों में 7 कार्यशालाओं का आयोजन किया गया।
7. संसदीय समिति द्वारा दिनांक 30 जून, 2022 को मंत्रालय का राजभाषा विषयक निरीक्षण किया गया। इसके उपरांत संसदीय समिति को दिए गए आश्वासनों पर मंत्रालय द्वारा शत-प्रतिशत कार्यवाई कर दी गई है।
8. मंत्रालय में राजभाषा कार्यान्वयन समिति का गठन कर लिया गया है और इसकी नियमित अंतराल में वर्ष में 4 बैठकें आयोजित की जा रही हैं और इन बैठकों में लिए गए निर्णयों पर अनुवर्ती कार्यवाई की जा रही है।
9. विगत 3 वर्षों के दौरान सितंबर माह में प्रत्येक वर्ष हिंदी पखवाड़ा का आयोजन किया जा रहा है। इस अवधि के दौरान विभिन्न हिंदी प्रतियोगिताओं व कार्यकलापों का आयोजन किया गया। गत वर्ष 2022 में हिंदी पखवाड़ा के समापन पर पुरस्कार विजेताओं को माननीय कौशल विकास और उद्यमशीलता राज्यमंत्री श्री राजीव चंद्रशेखर ने स्वयं उपस्थित होकर पुरस्कार विजेताओं को पुरस्कार व प्रमाण पत्र वितरित किए तथा उपस्थित अधिकारियों/कर्मचारियों का उत्साहवर्धन किया।

अपनी प्रस्तुति के अंत में संयुक्त सचिव महोदय ने अवगत कराया कि मंत्रालय के नए कौशल भवन में शीघ्र ही पुस्तकालय स्थापित किए जाने का प्रावधान किया गया है।

3. इसके पश्चात, अध्यक्ष महोदय की अनुमति से आमंत्रित माननीय सदस्यों से क्रमशः सुझाव/सलाह देने का आग्रह किया गया, जो इस प्रकार है:-

4. श्री रमेश बिधूड़ी, माननीय सांसद, लोकसभा:- माननीय सांसद महोदय ने बताया अधिकांश मंत्रालयों के अधिकारी बैठकों की कार्यवाही का आरंभ अंग्रेजी भाषा में करते हैं। बैठक में उपस्थित अन्य लोग इसका विरोध इसलिए नहीं करते कि कहीं उन्हें अशिक्षित न समझ लिया जाए। उन्होंने स्वास्थ्य मंत्रालय के सचिव का उदाहरण देते हुए कहा कि वे हमेशा बैठकों में हिंदी में बोलते हैं। उन्होंने सुझाव दिया कि मंत्रालयों/विभागों की बैठकों की कार्यवाही तथा चर्चा केवल हिंदी में ही होनी चाहिए। इससे एक अच्छा वातावरण बनेगा।

(कार्रवाई- समस्त अनुभाग)

5. श्री आदित्य प्रसाद, माननीय सांसद, राज्य सभा:- हम लोग हिंदी भाषा-भाषी क्षेत्र से आते हैं और हिंदी और अंग्रेजी अच्छी तरह समझ और बोल सकते हैं। माननीय प्रधान मंत्री जी के प्रयास से इस समय हिंदी के अनुकूल वातावरण बन गया है परन्तु जब हम कार्यालयों में जाते हैं तो पदाधिकारीगण अंग्रेजी को ही प्राथमिकता देते हैं। मेरा सुझाव है कि माननीय मंत्री जी जो शिक्षा मंत्री भी हैं, सभी राज्यों को निर्देश जारी करें विशेषकर झारखंड व उड़ीसा राज्यों में सभी अधिकारीगण अधिक से अधिक सरकारी कामकाज हिंदी में ही करें।

6. प्रो. कुसुमाकर पांडेय:- माननीय सदस्य ने सचिव महोदय को बधाई देते हुए कहा कि आपकी कार्यसूची देखने से प्रतीत हो रहा है कि आपके मंत्रालय में हिंदी में अच्छा काम हो रहा है, आपका काम बोल रहा है। ऐसा प्रतीत होता है कि हिंदी के प्रयोग की दिशा में हम बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। इसमें कोई संदेह नहीं है कि पिछले 9 वर्षों में पूरे देश में हिंदी का प्रचार-प्रसार बढ़ा है। सामान्य जीवन से लेकर तकनीक, व्यवसाय, संस्कृति आदि क्षेत्रों में हिंदी का प्रयोग बढ़ा है। मुझे इस बात की जानकारी नहीं है कि कितने मंत्रालयों की वेबसाइट द्विभाषी है। वेबसाइट का द्विभाषी होना सबसे महत्वपूर्ण कार्य है, आपके मंत्रालय ने इसे द्विभाषी कर लिया है, इसके लिए आप लोग बधाई के पात्र हैं।

7. श्री प्रभात कुमार:- कौशल विकास बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि जिस प्रकार की अवधारणा माननीय प्रधान मंत्री जी ने दी है, यह आवश्यक है कि कौशल विकास के माध्यम से हम उद्यमशीलता को बढ़ाएं। इसके लिए आवश्यक है कि कुछ अच्छी पुस्तकें हिंदी में प्रकाशित की जाएं। यह देखना होगा कि कैसे यह व्यवहार्य रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। मेरा सुझाव है कि पत्राचार करते समय वर्तनी के शुद्ध प्रयोग पर जोर दिया जाए और इसकी एकरूपता जैसी छोटी-छोटी बातें हैं जिन पर ध्यान दिया जाना चाहिए।

8. डॉ. अहिल्या मिश्र:- हैदराबाद निवासी माननीय सदस्य ने कहा कि मैं 'ग' क्षेत्र से आई हूँ और मैं संपूर्ण दक्षिण भारत का प्रतिनिधित्व करती हूँ। मेरा मानना है कि जब तक 'ग' क्षेत्र में हिंदी को अपनाया नहीं जाएगा तब तक हिंदी को देश भर में मान्यता कहने भर की बात होगी, करने की नहीं। उन्होंने आगे कहा कि हिंदी किसी क्षेत्र विशेष की भाषा नहीं है और जब यह सही अर्थों में 'ग' क्षेत्र की हो जाएगी तभी इसे समग्र रूप से अपनाया जा सकेगा। उन्होंने सुझाव दिया कि दक्षिण और पूर्वोत्तर की भाषाओं के कुछ शब्दों को हिंदी में मिलाया जाना चाहिए तभी हिंदी समृद्ध हो सकेगी। इस मंच के माध्यम से मैं भारत सरकार से अनुरोध करती हूँ कि इस दिशा में कुछ कार्य भी होना चाहिए।

9. प्रो. एन. ललिता:- कोयंबतूर से पधारी सदस्य ने सर्वप्रथम 'वनक्कम' कह कर सभी का अभिवादन किया। उन्होंने कहा कि मैं संसदीय कार्य मंत्रालय की हिंदी सलाहकार समिति की सदस्य हूँ और उसकी बैठक में भाग लेती हूँ। यह दूसरा मंत्रालय है, आप सब का काम देखकर प्रसन्नता हो रही है। धर्म को प्रधान करने वाले धर्मेंद्र प्रधान यहां अध्यक्ष के रूप में विराजमान हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि आपका हर काम धर्म के अनुसार ही होता होगा। आप सब देख रहे हैं कि भारत विश्वगुरु बनने की ओर अग्रसर है, यह सब देखकर अच्छा लग रहा है। मेरा सुझाव है कि द्विभाषी वेबसाइट में यदि प्रांतीय भाषा भी जोड़ दी जाए तो अच्छा होगा और इसे अनुवाद टूल का प्रयोग करके किया जा सकता है।

10.डॉ. सत्येंद्र सिंह:- माननीय सदस्य ने समिति को बताया कि वे अपने सेवाकाल के दौरान संसदीय समिति में रहे हैं और उन्होंने बहुत से कार्यों को देखा व समझा है। आज मैं यह जान कर पहली बार बहुत खुश हुआ हूँ कि इस मंत्रालय के राज्यमंत्री हिंदी पखवाड़ा जैसे छोटे कार्यक्रम में स्वयं उपस्थित हुए। यह बहुत बड़ी बात है। मंत्री जी जब ऐसे कार्यक्रमों में स्वयं जाते हैं, तो वहां पर कार्य करने वाले स्टाफ/कर्मचारियों को बहुत प्रेरणा मिलती है। नए कौशल भवन में पुस्तकालय की स्थापना के प्रस्ताव का उन्होंने स्वागत किया तथा अनुरोध किया कि नए पुस्तकालय में कौशल विकास से संबंधित तकनीकी पुस्तकें पर्याप्त मात्रा में रखी जानी चाहिए।

(कार्रवाई- सामान्य प्रशासन)

11. प्रो. मिलन रानी जमातिया:- माननीय सदस्य ने कहा कि वे पूर्वोत्तर भारत से आई हैं और पूर्वोत्तर के लोग हिंदी अच्छी तरह समझते हैं लेकिन लिखने में कुछ कठिनाई होती है। मेरा सुझाव है कि पूर्वोत्तर के युवाओं के लिए एक तकनीकी शब्दावली विकसित की जाए जिससे वे कौशल प्रशिक्षण से संबंधित विषयों को आसानी से समझ सकें।

12. श्री विनय कुमार दुबे:- माननीय सदस्य ने कहा कि वे महाराष्ट्र राज्य से आए हैं। उन्होंने एक शेर के साथ अपनी बात प्रारंभ की कि “पैर मेरे डगमगाए फिर भी चल रहा हूँ, चल रहा हूँ इस ध्येय से कि मैंने विश्व को न देखा रुकते हुए”। पिछले 9 वर्षों से हिंदी के प्रचार-प्रसार के लिए बहुत प्रयास किए जा रहे हैं। अपनी भाषा पर हमें गर्व है। आज यह जरूरी है कि हम अपने युवाओं को इसके प्रयोग के लिए प्रोत्साहित करें। विदेशी भाषाएं उन पर असर कर रही हैं। हिंदी एक दूसरे को जोड़े रखती है।

13. डॉ. अनीता नायर:- जयपुर से पधारी माननीय सदस्य ने कहा “सर्वे भवंतु सुखिनः सर्वे संतु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यंतु मा कश्चित् दुख भाग भवेत्” इसी भावना के साथ इस मंत्रालय की स्थापना हुई जहां कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय जन्म लेता है। जहां तक राजभाषा का प्रश्न है, यह मंत्रालय युवाओं को उनकी ही भाषा में प्रशिक्षण देकर एक बहुत बड़ा काम करता है। मंत्रालय की पीपीटी देखने के बाद यह पता चला कि आपके यहां हिंदी में बहुत अच्छा काम हो रहा है, फिर भी कुछ कमियां हो सकती हैं जिन पर चर्चा करने के लिए हम आज यहां एकत्र हुए हैं। उन्होंने आगे कहा कि दक्षिण और पूर्वोत्तर भारत में अभी और अधिक काम करने की आवश्यकता है। यह सरकार इस दिशा में बहुत अच्छा काम कर रही है। इसके लिए माननीय मंत्री महोदय व सरकार को साधुवाद। उन्होंने इस शेर के साथ अपना वक्तव्य समाप्त किया कि “परिंदों को मंजिल मिलेगी यकीनन, फैले हुए ये पर बोलते हैं, जो लोग रहते खामोश अक्सर जमाने में उनके हुनर बोलते हैं”।

माननीय राज्य मंत्री श्री राजीव चंद्र शेखर:- माननीय राज्य मंत्री जी ने माननीय सांसदों तथा विभिन्न प्रदेशों से पधारे हिंदी विद्वानों द्वारा मंत्रालय में हिंदी को और अधिक बढ़ाने के लिए दिए गए सुझावों का स्वागत किया तथा आश्वासन दिया मंत्रालय इनका अनुपालन करने का पूरा प्रयास करेगा। उन्होंने आगे कहा कि नए तकनीकी संसाधनों, विज्ञान की उपलब्धियों और अत्याधुनिक संचार-माध्यमों ने एक बार फिर से हिंदी में छिपी भावनात्मक एकता को साकार किया है। आज हमारे पास हिंदी से संचालित एलेक्सा है, अन्य स्वचालित मशीनें हैं, चैटबॉट हैं, जो हिंदी समझते हैं। वर्तमान समय में भाषाओं के विकास, उसके संचार के लिए

कृत्रिम मेधा (Artificial Intelligence) का साथ चलना समय की मांग है। हमारा मंत्रालय, राजभाषा विभाग द्वारा हिंदी के कार्यान्वयन और वार्षिक कार्यक्रम में उल्लिखित लक्ष्यों को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है। सभी प्रशिक्षण हिंदी में दिए जा रहे हैं तथा प्रशिक्षण सामग्री हिंदी व अंग्रेजी में तैयार की जाती है एवं परीक्षा हिंदी और अंग्रेजी में ली जाती है।

हमारा प्रयास होगा कि आज की इस बैठक में चर्चा के दौरान प्राप्त सुझावों पर अमल करके राजभाषा की उत्तरोत्तर प्रगति में महत्वपूर्ण योगदान दें।

माननीय मंत्री श्री धर्मेन्द्र प्रधान:- माननीय मंत्री जी ने अपने अध्यक्षीय संबोधन के प्रारंभ में सभी सदस्यों का बैठक में स्वागत करते हुए कहा कि मुझे संसद में रहते बहुत लंबा समय हो गया है, लेकिन मैं पहली बार देख रहा हूँ, आज बैठक में उपस्थिति लगभग शत-प्रतिशत है। इसके लिए माननीय सांसदगणों, अलग-अलग प्रदेशों से पधारे विद्वानों तथा विभागीय अधिकारियों को बैठक के विषय के प्रति व्यक्त प्रतिबद्धता को एवं प्रकट किए गए विचारों के लिए मैं विभाग की ओर से तथा भारत सरकार की ओर से आभार प्रकट करता हूँ। उन्होंने आगे कहा कि एक प्रस्तुति के माध्यम से तथा हमारे सहयोगी श्री चंद्र शेखर जी ने मंत्रालय से संबन्धित हिंदी की प्रगति का ब्योरा प्रस्तुत किया है। संयोग से मैं शिक्षा मंत्रालय भी देख रहा हूँ इसलिए आपको एक जानकारी देना चाहता हूँ कि हमने अभी हाल ही में 29-30 जुलाई को द्वितीय अखिल भारतीय शिक्षा समागम का आयोजन किया था। इसमें संयोग से माननीय प्रधान मंत्री भी इसे संबोधित करने पधारे थे। संयोग से यह राष्ट्रीय शिक्षा नीति की तीसरी वर्षगांठ भी थी। आपको यह सूचित करना चाहता हूँ कि एनसीवीईटी और डीजीटी की ओर से आईटीआई समूह के पाठ्यक्रमों की 100 पुस्तकों का 13 भारतीय भाषाओं में माननीय प्रधान मंत्री जी के कर कमलों से लोकार्पण किया गया। इनमें ज्यादातर हिंदी की हैं। इसके अलावा इंजीनियरी और डिप्लोमा पाठ्यक्रम चलाने वाला एआईसीटीई भी 13 भारतीय भाषाओं में कोर्स की किताबें बना चुका है जिनमें अधिकतर हिंदी की हैं। एनसीआरटी ने अपनी किताबें भारतीय भाषाओं में बनाने का नीतिगत निर्णय कर लिया है और सीबीएसई ने भी अपने पढ़ाने का माध्यम भारतीय भाषाओं में करने का नीतिगत निर्णय लिया है। मध्य प्रदेश में मेडीकल की पढ़ाई भी हिंदी में प्रारंभ हो गई है। भारत सरकार का राजभाषा विभाग और शिक्षा मंत्रालय मिल कर एक वृहत शब्दकोश बनाने की दिशा में काम कर रहे हैं जिसमें भारत की तमाम प्रांतीय भाषाओं के शब्दों को शामिल किया जाएगा। हमारा प्रगतिशील समाज है इसमें नई-नई चीजें जुड़ती जाती हैं। आज जो हिंदी का स्वरूप है कुछ सदी पहले नहीं था। हिंदी परिवर्तन के दौर से गुजरते हुए आज यहां तक पहुंची है। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में भी भारतीय भाषाओं को अधिक

महत्व दिया गया है। आजादी के उपरांत अंग्रेजी को लिंक भाषा के रूप में अपनाकर हम अटके रहे किंतु हम गुलामी की मानसिकता से पूरी तरह नहीं उबर सके। हमारा अंग्रेजी या अन्य किसी विदेशी भाषा से कोई बैर नहीं है। हमें यदि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जाना है तो हमें कई विदेशी भाषाएं सीखनी पड़ेगीं। इस देश में भारतीय भाषाओं को सीखने-सिखाने का माहौल बनाना था लेकिन प्रारंभ में ही हमारे देश में हिंदी और गैर-हिंदी का विवाद छेड़ दिया गया जो अंग्रेजों की डिवाइड एंड रूल पॉलिसी का एक हिस्सा था। आज जो लोग कहते हैं वे हिंदी क्यों सीखेंगे, वे उतने ही गलत हैं जितने वो लोग, जो कहते हैं कि आप हिंदी क्यों नहीं सीखेंगे। इसलिए नई शिक्षा नीति में यह कहा गया है कि सभी भारतीय भाषाएं राष्ट्रीय भाषा हैं। स्कूल, भाषा और प्रौद्योगिकी के समागम से नया समाज बन रहा है। इसमें हिंदी का महत्व स्वतःस्पष्ट है। यह एक सर्व स्वीकार्य तथ्य है कि हिंदी एक सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा है इसलिए इसका महत्व और अहमियत अपने आप सिद्ध हो जाती है। हमारे प्रधान मंत्री जी दुनिया भर में जहां कहीं भी जाते हैं वे हिंदी में ही बोलते हैं और प्रौद्योगिकी की मदद से सभी अपनी-अपनी भाषा में समझ पाते हैं। आज की भारत सरकार इस विषय को लेकर प्रतिबद्ध है। आप सभी लोग आज इस बैठक में आए और महत्वपूर्ण सुझाव दिए। आप सबका बहुत-बहुत आभार।

अंत में, सहायक निदेशक (राजभाषा) श्री सुखबीर सिंह ने माननीय मंत्री जी, राज्य मंत्री जी, सचिव महोदय, माननीय सांसदगणों, दूरदराज प्रदेशों से पधारे माननीय विद्वानों एवं मंत्रालय के अधिकारियों व अधीनस्थ कार्यालयों के प्रमुखों को बैठक में उपस्थित होने के लिए धन्यवाद दिया तथा बैठक की कार्यवाही की विधिवत् समापन की घोषणा की।

अनुलग्नक-1

कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय की हिंदी सलाहकार समिति की दिनांक 01.08.2023 को सायंकाल 06 बजे नई दिल्ली स्थित संसदीय सौंध के समिति कक्ष 'सी' में आयोजित पहली बैठक में उपस्थित सदस्यों की सूची:-

1.	श्री धर्मेन्द्र प्रधान, माननीय कौशल विकास तथा उद्यमशीलता मंत्री	अध्यक्ष
2.	श्री राजीव चंद्रशेखर, माननीय कौशल विकास तथा उद्यमशीलता राज्य मंत्री	उपाध्यक्ष
3.	श्री रमेश बिधूड़ी, माननीय सांसद, लोक सभा	सदस्य
4.	श्री आदित्य प्रसाद, माननीय सांसद, राज्य सभा	सदस्य
5.	डॉ. सिकंदर कुमार, माननीय सांसद राज्य सभा	सदस्य
6.	श्री अतुल कुमार तिवारी, सचिव, कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय	सदस्य
7.	डॉ. सत्येंद्र सिंह, प्रतिनिधि, केंद्रीय सचिवालय हिंदी परिषद	सदस्य
8.	प्रो. कुसुमाकर पाण्डेय, प्रतिनिधि, नागरी प्रचारणी सभा	सदस्य
9.	प्रो. मिलन रानी जमातिया, प्राध्यापक, त्रिपुरा विश्वविद्यालय, अगरतला	सदस्य
10.	प्रो. एन. ललिता, प्राध्यापक, भाषा विभाग, आर.वी.एस. महाविद्यालय, कोयंबतूर, तमिलनाडु	सदस्य
11.	डॉ. अहिल्या मिश्र, पूर्व-प्राचार्य, नवजीवन बालिका विद्यालय, हैदराबाद	सदस्य
12.	डॉ. अनीता नायर, प्राध्यापक, स्नातकोत्तर महाविद्यालय, जयपुर, राजस्थान	सदस्य
13.	श्री प्रभात कुमार, प्रभात प्रकाशन, नई दिल्ली	सदस्य
14.	श्री विनय कुमार दुबे	सदस्य
15.	श्री धनेश दवेदी, ओएसडी, सचिव, राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय	सदस्य
16.	डॉ. सुपर्णा एस.पचौरी, संयुक्त सचिव (राजभाषा-समन्वय) कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय	सदस्य सचिव
17.	सुश्री हेना उस्मान, (प्रशासन-स्थापना) कौशल विकास और	सदस्य

	उद्यमशीलता मंत्रालय	
18.	श्री नीलांबुज शरण, वरिष्ठ आर्थिक सलाहकार, कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय	सदस्य
19.	सुश्री त्रिशलजीत सेठी, महानिदेशक, प्रशिक्षण महानिदेशालय	सदस्य
20.	डॉ. निर्मलजी सिंह कलसी, अध्यक्ष, एनसीवीईटी	सदस्य
21.	डॉ. ललित शर्मा, निदेशक, भारतीय उद्यमशीलता संस्थान, गुवाहाटी	सदस्य
22.	डॉ. पूनम सिन्हा, निस्बड, नोयडा	सदस्य
23.	श्री वेद मणि तिवारी, सी.ई.ओ. एनएसडीसी	सदस्य
24.	श्री जे.के.सिंह, निदेशक, सामान्य प्रशासन, कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय	सदस्य
25.	श्री एन.आर. अरविंदन, निदेशक, केंद्रीय कर्मचारी प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान	सदस्य